



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 माघ 1940 (श0)  
(सं0 पटना 192) पटना, मंगलवार 5 फरवरी 2019

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त 2018

सं० 22/नि०सि०(डि०)-14-12/2016/1798—मो० रज्जन शमीम (ID-4535), तत्कालीन सहायक अभियंता, सोन नहर अनुमंडल, विक्रमगंज के पद पर पदस्थापन अवधि के दौरान उनके विरुद्ध 2002-03 एवं 2003-04 के लिए विभाग द्वारा पुनरीक्षित दर से कम दर पर चार्ट भूमि की बन्दोबस्ती करने एवं इसके फलस्वरूप सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया। आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में अर्न्तविष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

**आरोप सं०-01 :-** बिहार सिंचाई नियमावली और उसके अधीन निर्गत अनुदेशों के प्रावधान के अन्तर्गत चाट भूमि की बन्दोबस्ती प्रत्येक वर्ष 25 जून से 25 मार्च तक की अवधि के लिए नौ महीने के पट्टे पर, प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन किसानों को जल दर सहित समय-समय पर पुनरीक्षित विहित दरों पर किया जाना है। विभाग ने मार्च 2002 में एक/दो फसली चाट भूमि का बन्दोबस्ती के लिए दरों के पुनरीक्षण आदेश जारी किया।

भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 (रा०प्र०) की कंडिका 7.5 के अनुसार डिहरी प्रमंडल और सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज में देखा गया कि 5.115 एकड़ की दो फसली चाट भूमि की बन्दोबस्ती वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लिए विभाग द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित दर से काफी कम दर अर्थात् 213 रुपये प्रति एकड़ की दर से बन्दोबस्ती की गई, जिसके फलस्वरूप 48.60 लाख रुपये के कम राजस्व की वसूली हुई। सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाने के लिए दोषी हैं।

इसी क्रम में मो० रज्जन शमीम द्वारा अपने बचाव बयान में उल्लेखित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान सोन नहर अनुमंडल, विक्रमगंज में पदस्थापित नहीं थे। आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में उल्लेखित अवधि के दौरान मो० शमीम, सिंचाई प्रमंडल, देवघर में पदस्थापित थे। जिसमें उक्त मामला उनसे संबंधित ज्ञात नहीं होता है।

मो० शमीम से प्राप्त बचाव बयान पर विभागीय पत्रांक-2442 दिनांक-18.11.2016 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी से मंतव्य की माँग की गई। जिसके आलोक में मुख्य अभियंता के पत्रांक-1011 दिनांक-20.05.2017 में संलग्न अधीक्षण अभियंता के पत्रांक-430 दिनांक-28.03.2017 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि

मो० रज्जन शमीम, अवर प्रमंडल पदाधिकारी के रूप में वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रमगंज में पदस्थापित नहीं थे।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-50/AS, दिनांक-12.06.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें मो० रज्जन शमीम, तत्कालीन सहायक अभियंता का वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में सोन नहर अवर प्रमंडल, विक्रमगंज में पदस्थापित नहीं थे। इसलिए उक्त आरोप से असम्बद्ध है। अतः आरोप अप्रमाणित है।

मो० शमीम से प्राप्त बचाव बयान मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के द्वारा संदर्भित मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षापरांत मो० रज्जन शमीम, तत्कालीन सहायक अभियंता को असम्बद्ध होने के कारण आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

मो० रज्जन शमीम को उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में गठित आरोपों से असम्बद्ध होने के कारण आरोप से मुक्त करने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
चन्द्रमा प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 192-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>